

जादुमणि सिंह, पवन बर्तवाल आसान जीत के साथ फाइनल में



ग्रेटर नोएडा, 9 जनवरी। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल के सिल्वर मेडलिस्ट जादुमणि सिंह ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एलीट पुरुष और महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 50–55किग्रा कैटेगरी के सेमीफाइनल में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अमित पंघाल को हराकर पवन बर्तवाल के साथ एक रोमांचक फाइनल मुकाबले के लिए जगह बनाई। यह पहली बार है जब पुरुष और महिला नेशनल चैंपियनशिप एक ही जगह पर एक साथ हो रही है और देश भर से 600 बॉक्सर पुरुष और महिलाओं के लिए 10–10 वेट कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। सेमीफाइनल में, जादुमणि ने अमित पर 5:0 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि पवन ने मणिपुर के विक्रम सिंह पर भी इसी तरह की जीत हासिल की। इस बीच, ऑल इंडिया पुलिस की विश्व चैंपियन मीनाक्षी (महिलाओं की 45–48 किग्रा) ने मध्य प्रदेश की मलिका मोर को 5:0 से हराया, जबकि निकहत (48–51 किग्रा) ने यूपी की कुसुम बघेल के खिलाफ 4:1 के स्प्लिट फैसले से अपनी सेमीफाइनल जीता। टोक्यो ओलिंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोर्गोहेन भी महिलाओं की 70–75किग्रा कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई, उन्होंने उत्तर प्रदेश की इमरोज खान को 5:0 से हराया, जबकि प्रीति (51–54 किग्रा) ने उत्तराखंड की आरती धरियाल को 5:0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के सेक्शन में, सचिन (55–60 किग्रा) ने पंजाब के भूपिंदर सिंह को हराया, जबकि राजस्थान के विवेक, हितेश गुलिया (65–70 किग्रा) के सामने टिक नहीं पाए। इसके अलावा, अपनी-अपनी कैटेगरी के फाइनल में पहुंचने वालों में अविनाश जमवाल (60–65 किग्रा), सुमित (70–75 किग्रा) और नरेंद्र (90 किग्रा) शामिल हैं।

खेल संघों से जुड़े विवादों का अब समाधान होना चाहिए : मांडविया

अहमदाबाद (गुजरात), 9 जनवरी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि खेल संघों से जुड़े विवादों का अब समाधान होना चाहिए।

राजधानी

गांव-ढाणी तक मिल रहा गुणवत्तापूर्ण इलाज : सी.एम. भजनलाल शर्मा

चिकित्सा और स्वास्थ्य पर बजट पूर्व चर्चा हुई

■ **मुख्यमंत्री ने कहा बजट पूर्व संवाद का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों से एक ऐसा बजट बने, जिससे प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलें**

■ **अब तक 37 लाख मरीजों को 7 हजार 300 करोड़ रुपये का कैंसलस इलाज उपलब्ध करवाया**

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और संवेदना से जुड़ा क्षेत्र है। विगत दो वर्षों में राज्य सरकार ने अपने बजट में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

आगे भी स्वास्थ्य के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया है। इससे गांव-ढाणी तक प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क उपचार मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि बजट पूर्व संवाद का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों से एक ऐसा बजट बने, जिससे प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और राजस्थान स्वास्थ्य में सिरमौर बने। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार 'पहला सुख निरोगी काया' अर्थात् स्वस्थ शरीर

ही सबसे बड़ा सुख होता है। इसी अवधारणा के साथ प्रदेश में लांगू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब तक 37 लाख मरीजों को 7 हजार 300 करोड़ रुपये का कैंसलस इलाज उपलब्ध करवाया गया है। इसी तरह, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत औषधियां, सर्जिकल एवं सुर्चस उपलब्ध करवाने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए रामाश्रय वार्ड खोले हैं, जहां उन्हें सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। शर्मा ने कहा कि हमारी

सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि प्रदेश को प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 15 नवीन मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निचले स्तर तक चिकित्सा सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विगत दो वर्षों में 7 उप जिला अस्पताल, 2 सैटेलाइट अस्पताल, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 14 संस्थानों का जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन तथा 7 नवीन सैटेलाइट अस्पतालों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि 129 उप स्वास्थ्य केंद्रों को

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नयन किया है। करीब 8 हजार 700 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया एवं 412 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए गए।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवरसर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी एवं आईएलबीएस हॉस्पिटल, नारायणा हरदयाल ग्रुप, महावीर चिकित्सा सेवा समिति, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, यूनीसेफ, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, आईएमए राजस्थान, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं आरयूएचएस के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने किया रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के हितधारकों से संवाद

■ **मुख्य सचिव ने आईटीआई अधिकारियों को अपने-अपने संस्थानों में संचालित ट्रेड्स तथा प्रस्तावित नए ट्रेड्स की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए**

जयपुर। राजस्थान में प्रधानमंत्री स्किलिंग और रोजगार ट्रांसफॉर्मेशन (पीएम सेतु) के पायलट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा इसके पहले चरण में प्रोजेक्ट को भिवाड़ी, बालोतरा, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा जिले को लेने को मंजूरी दी गई है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के बेहतर शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

इसी दिशा में सरकार द्वारा समयबद्ध एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए सरकारी क्षेत्र में 4 लाख तथा निजी क्षेत्र में 6 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार सृजित करने के संकल्प पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में उद्योग-आईटीआई के प्रदेश के आईटीआई को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित करने की दिशा में टोस प्रयास किए जाएं। इस अवसर पर उन्होंने झालावाड़ आईटीआई को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए

प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के अधिक से अधिक आईटीआई को उद्योगों में जोड़ा जाए, जिससे विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ उद्योगों की व्यावहारिक समझ भी प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों के नवाचारों एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाया जाए तथा प्रदेश के आईटीआई को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित करने की दिशा में टोस प्रयास किए जाएं। इस अवसर पर उन्होंने झालावाड़ आईटीआई को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए

बधाई देते हुए अन्य आईटीआई को भी इसी प्रकार कार्य कर शिक्षा के स्तर में निरंतर सुधार लाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव ने संस्थान प्रबंधन समितियों को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आईटीआई अधिकारियों को अपने-अपने संस्थानों में संचालित ट्रेड्स तथा प्रस्तावित नए ट्रेड्स की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी आईटीआई के दीक्षांत समारोह की जानकारी साझा कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित करने के निर्देश दिए।

बैठक में सदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग , पी. रमेश शासन सचिव श्रम विभाग, टीना सोनी शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, ऋषभ मंडल, आयुक्त कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों के आईटीआई प्राचार्य एवं अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

सुरेन्द्र सिंह शाहपुरा एफएचटीआर के अध्यक्ष बने



जयपुर। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) की वार्षिक आम सभा का 8 जनवरी को जयपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सर्वसम्मति से नई प्रबंधन समिति का निर्वाचन किया गया, जिससे संगठन में एक नए नेतृत्व काल का शुभारंभ हुआ। एफएचटीआर के अध्यक्ष पद हेतु सुरेन्द्र सिंह शाहपुरा का निर्वाचन किया गया, जबकि तरुण कुमार बंसल को महासचिव चुना गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह तथा संयुक्त सचिव हेमन्त मित्तल को नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह शाहपुरा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई समिति राजस्थान के पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को नवाचार, समन्वय तथा प्रभावी प्रतिनिधित्व के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों को लेकर राज्य सरकार से 19 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह व जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश मुन्नालाल शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर

संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। पंचायत पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में कहा कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में नियमों व दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है और इससे स्थानीय नागरिकों व पंचायत

प्रतिनिधियों के अधिकारों की अवहेलना हुई है। ऐसे में पंचायतों की सीमाओं में किए गए बदलावों से प्रशासनिक असुविधा होगी और आमजन की मूलभूत सुविधाओं तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ

अधिवक्ता हनुमान चौधरी, लक्ष्मीकांत मालपुरा और प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया में जनसुनवाई और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की अनदेखी कर संशोधित अधिसूचनाएं जल्दबाजी में जारी की हैं।

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग (पीएचईडी) में रिपेयर, पाइपलाइन लीकेज सुधार और लैंड संपर्क से हुए झालावाड़ के अधीक्षण अभियंता (एसई) विष्णु चंद गोयल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने परिव्रादी से बकाया बिल पास करने और परेशान न करने की एवज में 84 हजार रुपए कीमत का आईफोन एक्सआर मोबाइल रिश्वत के रूप में लिया। एसीबी पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि झालावाड़ टीम को 5 जनवरी

2026 को एक ठेकेदार ने शिकायत दी थी। परिव्रादी ने बताया कि वह पीएचईडी खंड झालावाड़ में हैंडपंप रिपेयर, पाइपलाइन लीकेज सुधार और लैंड संपर्क से जुड़े कार्य कर रहा है। पूर्व में रिजस्ट्रेशन के नाम पर उससे 25 हजार रुपए वसूले जा चुके हैं। इसके बाद वह उसके पार्टनर को बार-बार परेशान कर काम से हटाने और डिबार करने की धमकियां दी जा रही थीं। परिव्रादी के अनुसार अगस्त माह से उससे आईफोन मोबाइल की मांग की जा रही थी। लेबर बिल को फर्जी बताकर भुगतान रोक दिया गया और

त्योहारों पर 'कुछ नहीं देने' की बात कहकर दबाव बनाया गया। इस पर जब परिव्रादी अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल से मिले तो उन्होंने बकाया बिल पास करने और भ्रष्टाचार में परेशान न करने की एवज में आईफोन 16 प्रो मोबाइल की मांग की, जिसकी कीमत करीब 1.30 से 1.50 लाख रुपए बताई गई। शिकायत के आधार पर 7 जनवरी 2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया, जिसमें मोबाइल फोन की रिश्वत मांग की पुष्टि हुई।